यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/122/2020 **दिनांक :** 28.07.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

ऋण चूककर्ताओं और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ एआईबीईए का अभियान

उपरोक्त विषय में हम एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 28/220/2020/58 दिनांक 25.7.2020 का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

ऋण चूककर्ताओं के खिलाफ तथा बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हमारा अभियान

इकाईओं और सदस्यों को ज्ञात है कि बैंक राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग के बचाव में हमारे अभियान के एक भाग के रूप में और कॉर्पोरेट खराब ऋणों को वसूल करने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए, हमने 2426 जानबूझकर चूककर्ताओं की सूची जारी की जो हमारे बैंकों के रू. 147,350 करोड़ के देनदार हैं। हमने बैंकों के निजीकरण के किसी भी कदम के खिलाफ भी अपनी आपत्ति दर्ज की है जैसा कि प्रैस और मीडिया में बताया जा रहा है।

जानबूझकर चूककर्ताओं, जो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, के नामों की सूची को प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में अच्छी तरह से कवर किया गया है और इस प्रकार इन सूचनाओं को बड़े पैमाने पर लोगों की जानकारी में लाया गया है। इन सूचनाओं पर कई राजनैतिक हस्तियों, श्रम संगठन नेताओं और कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों का भी ध्यान गया है। वे जानबूझकर चूककर्ताओं पर कार्रवाई करने की हमारी मांग के समर्थन में अपने ट्वीट कर रहे हैं।

श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता ने ट्वीट किया : ''2,426 कंपनियों ने बैंकों से लोगों की बचत के 1.47 लाख करोड़ रूपये लूट लिए। क्या यह सरकार इस लूट की जांच करेगी और दोषियों को सजा देगी ? ''या यह उन्हें नीरव और ललित मोदी की तरह भागने देगी ?''

श्री डेरेक ओ'ब्रायन, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद और नेता ने ट्वीट किया : ''इस सरकार की सोच बहुत स्पष्ट है। गरीबों से लें और अमीरों को दें। शीर्ष 33 चूककर्ता सामूहिक रूप से भारतीय बैंकों के बकाया कुल रू. 1.47 लाख करोड़ में से रू. 32,737 करोड़ के देनदार हैं। एआईबीईए से मुझे प्राप्त निंदनीय सूची को देखें, कुछ असली रत्न''।

जारी पृष्ठ 2

एक और ट्वीट में उन्होंने कहा है : ''आज एआईबीईए से 2426 जानबूझकर चूककर्ताओं की एक सूची प्राप्त हुई। आम आदमी से रू. 1,47,350 करोड़ लूटे गए। प्रत्येक बेरोजगार प्रवासी कामगार को लाखों रूपये स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त हैं। भारतीय बैंकों द्वारा सामना की गई चूक की राशि को साक्षा करना। सरकार हमारे लोगों की कीमत पर घनिष्ठ पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है''।

साथी डी. राजा, पूर्व सांसद और महासचिव, सीपीआई ने अपने टेलीफोन संदेश में बैंक ऋणों के जानबूझकर चूककर्ताओं की सूची जारी करने के लिए एआईबीईए को बधाई दी और मांग की कि सरकार को बट्टे खाते डालने के जरिए उन्हें रियायतें देने के बजाय इन चूककर्ताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए।

साथी सीताराम येचुरी, पूर्व सांसद और सीपीआई–एम के महासचिव ने ट्वीट किया : ''यह बैंकों में जमा लोगों की जीवन भर की बचत की लूट है। चूककर्ताओं की सभी संपत्तियों को जब्त करें और लोगों का पैसा लौटायें। मोदी के घनिष्ठ मित्रों को लूटने और निकल भागने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें गिरफ्तार करें''।

साथी दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई–एमएल के नेता ने ट्वीट किया : ''भारत के बैंक कर्मचारियों के साथ एकजुटता में जो निजीकरण और कॉर्पोरेट तुष्टिकरण के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। आपके संघर्षों को और अधिक शक्ति।''

एटक की महासचिव, साथी अमरजीत कौर, ने अपने वीडियो वॉयस संदेश में, 1960 के दशक में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संघर्ष के लिए और अब बैंकों के निजीकरण के विरोध में एआईबीईए द्वारा निभाई गई महान भूमिका को याद किया। उन्होंने चूककर्ताओं की सूची के प्रकाशन का स्वागत किया और चाहती थी कि सरकार इन कॉर्पोरेट चूककर्ताओं से सख्ती से निपटे।

साथी एस आर दारापुरी, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और इंडियन पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि सरकार को चूककर्ताओं से इन खराब ऋणों को तुरन्त वसूलना चाहिए और इसे बैंकों को वापस करना चाहिए और साथ ही बैंकों के निजीकरण को रोकना चाहिए।

साथी बिनॉय विष्वम्, सांसद और सचिव, सीपीआई ने एआईबीईए द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए और बैंकों के निजीकरण के कदमों को रोकने की मांग करते हुए वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। (उनके पत्र की प्रति यहां प्रस्तुत है)।

साथियों, हमें अपने अभियान को जारी रखना चाहिए और जितना संभव हो उतना सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करना चाहिए।

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री